

उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने की दस्तक सह डायरिया अभियान की शुरआत

स्वास्थ्य विभाग को मिलेगी 20 हजार की एडिशनल मैन पॉवर

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। राजधानी भोपाल में मंगलवार को दस्तक सह डायरिया अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि हमारे पास जो भी लोग आते हैं, वह कहते हैं कि बिलिंग तो लोची है। डॉक्टर्स भी दे दीजिए, पैरेमेडिकल स्टोर्स भी दे दीजिए। यह चुनौती हमारे सामने थी। अगले छह महीने में 20 हजार एडिशनल मैन पॉवर स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाला है। अब हमें काम करना है। बिलिंग इंकिप्मेंट और मैन पावर देने की जिम्मेदारी सरकार की है। पर्कर्फॉर्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा, 0 से पांच साल के बच्चे हमारी भविष्य हैं। इनको बचाने का काम हमारी टीम का है। निश्चित रूप से यह जो कार्यक्रम है, इसका क्रियान्वयन आपके ऊपर है। मेरा छोटा बेटा जब दो महीने का था, तब से उसके हार्ट में कुछ दिक्कत आयी। उसकी बीमारी की पहचान दो महीने में हो गई तो समय से इलाज शुरू हो गया। आज वह स्वस्थ है। हाल ही में मैंने आठ महीने की एक बच्ची को देखा। उसकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जैसे हमारे बच्चे हैं। ऐसे इस प्रदेश के जितने बच्चे हैं, उनकी चिंता आप सभी करेंगे।

31 जून तक प्रदेश घर में चलेगा दस्तक अभियान।

मध्यप्रदेश में डायरिया से निपटने के लिए 25 जून से 31 अगस्त तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बाल्य कालीन बीमारियों की पहचान एवं त्वरित उचाचर सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में प्रतिवर्ष दस्तक अभियान संचालित किया जाता है। अभियान का प्रमुख उद्देश्य बाल मृत्यु प्रकरणों में कमी लाना है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के भी जिलों के सीएम-ओं को बुलाया गया था।

ऐसे चलेगा दस्तक अभियान।

स्वास्थ्य आयुक्त प्रियंका दास ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों में स्वास्थ्य विसंगतियों की जाएगी पहचान। दस्तक अभियान के अन्तर्गत बीमार नवजात और बच्चों की पहंच, प्रबंधन एवं रेफरल एवं अस्पताल से छुट्टी प्राप्त बच्चों का फॉलोअप किया जाएगा। नो महीने से 5 वर्ष के बच्चों में विटामिन हाइएल की खुराक का अनुपूरण और 0 से 5 आयु वर्ष के बच्चों में दस्तक की पहचान एवं नियंत्रण के लिए ओआरएस एवं जिंक का वितरण स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा किया जाएगा। 31 जून तक प्रदेश भारत में दस्तक अभियान चलाया जाएगा।



डायरिया की रोकथाम के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, ग्रामीण विकास एवं आवास विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि दस्तक के मामलों को ट्रैक करने के लिए जिला

सरीरी टीम का गठन करें। ऐसे क्षेत्र जहां दस्त एवं अन्य रोगों के मरीजों की अधिकता हो उस क्षेत्र का नियमित रूप से डेटा और अपराध स्थापित करना सुनिश्चित करें। बच्चों में दस्त को रोगों के लिए रोटा वायरस टीकों को बढ़ावा दें और उनका प्रबंध करें। सभी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में पर्यांत मात्रा में औरल रिहाइंशन

सोल्यूशंस और जिंक सफ्टीमेंट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करें व सभी शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में औआरएस कॉर्नर स्थापित करना सुनिश्चित करें। सभी शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में डायरिया प्रबंधन के लिए बिस्टर विहारिकृत करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए की आमजन को प्रदाय किए जाने वाला जल संक्रमित न हो। विशेष रूप से ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में सेनिटेशन सुविधाओं में सुधार करें। खुले में शौच को रोकने के लिए शौचालयों का निर्माण और उपयोग को बढ़ावा दें। जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए चिरा चंगह और निपाटन प्रणाली को बढ़ावा दें। खाद्य प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों में स्वास्थ्य और स्वच्छता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करें। जन सामान्य

आपातकाल की 50वीं बरसी पर मीसाबदियों को सम्मानित किया गया।

नरोत्तम बोले-संकट लोकतंत्र पर नहीं गांधी परिवार पर है

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। भारीय जनना पार्टी प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को आपातकाल की 50वीं बरसी पर मीसाबदियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व गृहमंत्री और वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मिश्र ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता सोमवार को संसद में संविधान की प्रति हाथ में लेकर पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व संविधान को किए खतरा नहीं है। इन्होंने बोला-प्रचार-प्रसार किया। हकीकत में कांग्रेस राज में 100 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन किया गया। जब 1975 में आज के दिन रात को 2 बजे तकालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागाई थी। उस समय सोनिया गांधी बहू के नाते वहां पर पौजूड़ थी। तब सोनिया गांधी ने संविधान बचाने की बात नहीं की, लेकिन सोमवार जब संसद में पहुंची तो उनके हाथ में



संविधान की प्रति थी। प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व संविधान को किए खतरा नहीं है। इन्होंने बोला-प्रचार-प्रसार जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। हमें उसका सच बताना होगा। मोदी जी ने देश के बेटों को चुना, इंडी गठबंधन ने अपनों को चुना। डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि राहुल गांधी झूल की मशीन है। संकट संविधान और लोकतंत्र पर नहीं है, बल्कि राहुल और गांधी परिवार के साथ-साथ अपने परिवार के आधार पर की गई है। यह उदाहरण इसके आधार पर की गई है।

किसके आदेश पर हटाई जीनत उल मसाजिद से जालियां, होगा जांच

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। जीनत उल मसाजिद शहर और प्रदेश की कदमी मस्जिदों में शुमार की जाती है। यह नवाबकालीन विरासत का एक हिस्सा है। इसके बजाए जीनत उल मसाजिद को अल्टरेट एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके संबंध में आपातिक प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल में प्रचलित है। रायपुरिया के गवन की गई शासकीय सेवा शर्तों के स्थापित करने वाले इंडी गठबंधन

पर हैं। प्रधानमंत्री ने हमेशा देश के बेटों को स्थापित करने के लिए उन्होंने और कांग्रेस के लिए एक-दूसरे को चुना है। पिछले तीन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने शासकाल को किए गए विकास कार्यों का जिक्र नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आरक्षण-संविधान और लोकतंत्र खतरे में है इसको लेकर इन्होंने बोला-प्रचार किया। तमिलनाडु में कांग्रेस की प्रदेश भर के जिला मुख्यालय को सौंपेंगे। त्रिपाठी ने बताया कि मप्र में निर्सिंग माहोदायलों के दबाने के लिए भाजपा सरकार प्रयासरत है। परंतु आगामी मौत हो गई, लेकिन एक भी इंडी

गठबंधन का कोई नेता कुछ नहीं बोला। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां कुछ होता है तो संविधान और लोकतंत्र को खतरा बताने लगते हैं। हम बाल साहेब डॉ. अंबेडकर के अनुयायी हैं। हमारे शासन में संविधान को कोई खतरा नहीं हो सकता है।

आपातकाल में न कोई अपील चलती थी न कोई दलील। पार्टी के प्रदेश कांग्रेस-महामंत्री विधायक भाजपा नदी तक आये हैं। उन्होंने उनको लेकर इन्होंने बोला-प्रचार किया। उनको लेकर इन्होंने उनको लेकर इन्होंने बोला-प्रचार किया। उन्होंने सिर्फ आरक्षण-संविधान और लोकतंत्र पर जांच की जाएगी।

को जांच के लिए निर्देशित कर दिया गया है। गोंत्रलब है कि शहर की कदमी मस्जिदों में शुमार जीनत उल मसाजिद से जालियां हटाई जीनत उल मसाजिद को अनुमति ली जाना चाहिए थी। मप्र वक्फ बोर्ड के अधीन काम करने वाला शाही औरकाप लगातार मानवान्की की जारी रखता रहा है। उपरान्त उल मसाजिद को अनुमति दिया गया है।

जीनत उल मसाजिद को अनुमति दिया गया है। उपरान्त उल मसाजिद को अनुमति दिया गया है।

जीनत उल मसाजिद को अनुमति द

सम्पादकीय

कई सवाल खड़े करते हैं
लगातार धड़ाधड़ गिरते पुल

निर्माण उद्योग कई विकासशील देशों में आर्थिक विकास की रीढ़ है। बृन्दावनी द्वारे की परियोजनाओं में सालाना खर्च किए जाने वाले धन की मात्रा को देखते हुए, भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी की गुंजाइश बहुत अधिक होती है। सरकारों के लिए अधिक उपयोग की आवश्यकता निर्गत नहीं थी। अब इसकी जानकारी को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए अधिक ज्ञानों की आवश्यकता है।

निर्माण उद्योग कई विकासशील देशों में आर्थिक विकास की रीढ़ है। बृन्दावनी द्वारे की परियोजनाओं में सालाना खर्च किए जाने वाले धन की मात्रा को देखते हुए, भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी की गुंजाइश बहुत अधिक होती है। सरकारों के लिए अधिक उपयोग की आवश्यकता निर्गत नहीं थी। भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा उदाहरण बरसात आने से पहले ही बिहार में एक सप्ताह के भीतर एक के बाद एक तीन पुलों का गिरना है। यह सार्वजनिक निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार व धांधलियों को बेनकाब करता है। लगातार धड़ाधड़ गिरते पुल न केवल ठेकेदारों बल्कि उन्हें संरक्षण देने वाले राजनेताओं पर भी सवालिया निशान लगते हैं। एक सप्ताह के भीतर बिहार के मोतिहारी में रविवार को एक पुल गिरने की तीसरी घटना हुई। इससे पहले अररिया और सिवान में भ्रष्टाचार के पुल गिरे थे। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में डेढ़ करोड़ की लागत से बनने वाला जो पुल गिरा, उसकी एक दिन पहले ही छार्टार हुई थी। रात में पुल भरभरा कर गिर गया। यदि यह पुल जाली रखने के बाद गिरता तो न जाने किसी जाने वाले जारी रखनी। आरोप है कि बिट्टा सामग्री के कारण पुल बनने से पहले गिर गया। शनिवार को सिवान में गंडक नहर पर बना तीस फीट लंबा पुल गिर गया, जो चार दशक पहले बना था। इसी तरह मंगलवार को अररिया में बारह करोड़ की लागत से बना पुल गिर गया था। पुल के तीन पाये ध्वस्त हो गए थे। बिहार में निर्माण कार्यों में धांधलियों का आलम यह है कि पिछले पांच सालों के दौरान दस पुल निर्माण के दौरान या निर्माण कार्य पूरा होते ही ध्वस्त हो गए। उल्लेखनीय है कि बीते साल जून में भगलपुर में गंगा नदी पर करीब पाँच दिन जहार करोड़ की लागत से बन रहे पुल के गिरने पर भारी शोर मचा था। लेकिन उसके बाद भी हालात नहीं बदले। पुलों के गिरने का सिलसिला यूं ही जारी है। जो उत्तरांश है कि नियम-कानून ताकि रखकर बेंखूफ बिट्टा सामग्री वाले सार्वजनिक निर्माण कार्य जारी हैं। जाहिर है कि उसके बाद गिरते ही अधिकतम इमरजेंसी का लागू होना संभव है।

सवाल यह उठता है कि आजादी के सात दशक बाद भी हम देश की विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले तत्त्व क्यों विकसित नहीं कर पाए? यह जरूरी है कि सार्वजनिक निर्माण गुणवत्ता का हो और उसका निर्माण कार्य पूरा हो। इन ज्ञानों को इस तरह डिजिन किया जाए, जिसके कई पैदियों को उसका लाभ मिल सके। साथ ही वह दुर्बिनता और जनता की सीधी विवाद बढ़ावा देता है। मार विंडोवा देखिये कि बिहार के पुल उद्भव से पहले ही ध्वस्त हो गया था। उल्लेखनीय है कि मोटे मुनाफे के लिए बिट्टा निर्माण कार्य सम्पादित होता है। अब तो अनुच्छेद 356 का बेजा इस्तेमाल भी संभव नहीं है। यही नहीं सुधीरन कोर्ट को इन परिस्थितियों की समीक्षा करने का पूरा अधिकार हो गया है।

संविधान संशोधन-44 और न्यायिक समीक्षा के साथ ही जनजागरूकता के चलते अब असाधारण युद्धकालीन या संस्कृत विद्रोह की स्थिति के अलावा आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। असाधारण आर्थिक संकट में भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हानि नहीं की जाती है। यह स्थिति आपातकाल के बाद सुधीरन कोर्ट भी संपर्क कर चुका है। दरअसल, सचर के दशक में जब देश आपातकाल की ज्यादातीय और नायिक अधिकारों के हनन से कराह रहा था तो 1977 के आम चुनाव में उन्हें ज्यादातीयों के गर्भ से जनता पार्टी के शासन के प्रावधान के रूप में एक ऐसे जनादेश का जन्म हुआ जिसकी पहली प्राथमिकता आपातकाल की ज्यादातीयों की संभावनाओं को सदा के लिये समाप्त करने की थी।

जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में अपने घोषणापत्र में भी 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाप्त कर आपातकाल लागू होने से पहले की संविधान की स्थिति बहाल करने के बायाद कोर्ट के साथ ही ऐसी नई व्यवस्था की बात कही जाती है कि इस बाद पर नागरिकों का अधिकारों का बहाल होना न कर सके। यह संविधान संशोधन संविधेय विधेयक तत्कालीन कानून मंत्री शांति भूषण द्वारा 16 दिसंबर 1977 को लोकसभा में पेश किया गया था जिसमें संविधान के 30 से अधिक प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव था। इसमें 42वें संशोधन के प्रस्तावों को हटाने के प्रस्ताव भी थे। चूंकि संविधान संशोधन में राज्यसभा

अफगानिस्तान में महिलाओं की दुर्दशा... विश्व समुदाय को ठोस कदम उठाने की जरूरत

अफगानिस्तान में तालिबान को तीसरा साल हो गया है। 15 अगस्त, 2021 को उड़ने वाली दुसरी बार सत्ता पर कब्जा किया था। उम्मीद की जारी रही थी कि महिलाओं के प्रति उनके रखैये में तब्दीली आएगी। उनको शिक्षा पाने की इजाजत भी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत समेत ऐसे बहुत से देश हैं, जो महिलाओं को शक्तिशाली बनाने में लगे हुए हैं। लोकसभा और नायिक सम्बाधों में महिलाओं के गुणवत्ता की जारी रही है, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान में महिलाओं को कोड़े मारे जाते हैं। हाल ही में तालिबान द्वारा 14 महिलाओं और 60 से ज्यादा लोगों को दंड के तौर पर सार्वजनिक तौर पर कोड़े मारे गए। जिसकी सारी दुनिया में निर्दा हो रही है। उल्लेखनीय है कि तालिबान के 1990 के दशक के शासन में भी यही होता था। संयुक्त राष्ट्र की संस्थायां यूनेनेचर्स और नेटवर्क ने कानूनी धर्मों के लिए जारी कर दिए वैश्विक कार्रवाई की मांग की है। और कहा है कि तालिबान के शासन के 41 से ज्यादा मामलों में आपाने एआई, जिसमें 58 महिलाएं और 274 मर्द और बच्चों को अलग-अलग अपराधों के लिए कोड़े मारे गए। नाबालिग और कमसिन वच्चियों को दर्शन शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। लड़कियों में खुल्कुशी करने की प्रवृत्ति काफी बढ़ रही है। तालिबान ने सत्ता संभालने वाला किया था कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन वे घर से

अब आसान नहीं रह गया देश पर इमरजेंसी थोपना

25 जून 1975 को जब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी तो उस समय के अधिकारीं मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को इसकी जानकारी नहीं थी। आज फिर अधोषित इमरजेंसी का आरोप गाहे-बगाहे लगता रहता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आज घोषित या अधोषित इमरजेंसी का लागू होना संभव है?

भारत में अंतिम बार आपातकाल की घोषणा हुए 49 साल गुजर गए, मगर उस दौर की ज्यादातीयों की यादें आज भी राजनीतिक क्षेत्रों में गूंजती रहती हैं। खासकर प्रेस की सत्रत्वता के हनन के लिए वह दौर एक ताराहरण बन गया। 25 जून 1975 से लेकर 21मार्च 1977 तक चले इतिहास के उस काले दौर से भी पहले देश में युद्धों के दौरान आपातकाल की घोषणाओं हो चुकी थीं जो कि वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अपरिहार्य थीं जिनको लेकर देशवासियों को काई ऐतराज नहीं हुआ। लेकिन जून 1975 के आपातकाल की घोषणा से सारा देश इतना विचलित हुआ कि न केवल तत्कालीन सत्ताधारी दल को अपितु तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी जनता ने हरा कर सबके लिए इमरजेंसी का लागू होना संभव है?

भारत में, अंतिम बार आपातकाल की घोषणा से खासकर बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरे में हैं तो राष्ट्रपति की मंजूरी और आधे से अधिक राज्यों से रेटिफिकेशन के बाद इसको तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेडी की स्वीकृति 30 अप्रैल 1979 को मिल सकी। 25 जून 1975 को जब राष्ट्रपति की घोषणा की गई थी तो उस समय के अधिकारीं में कोई शासक या प्रधानमंत्री चाहक भी 1975 वाला आपातकाल देश पर लागू नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान के 44वें संशोधन के बाद आपातकाल की घोषणा की गोपनीय नहीं है। जबकि इतना बड़ा फैसला कैबिनेट की समस्ति पर आपातकाल की स्वीकृति दी थी।

संविधान संशोधन-44 और न्यायिक समीक्षा के साथ ही जनजागरूकता के चलते अब असाधारण युद्धकालीन या संस्कृत विद्रोह की स्थिति के अलावा आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। असाधारण आर्थिक संकट में भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हानि नहीं की जाती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 के तहत गांटीकृत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को विचलन का अधिकार प्राप्त है इससे उस समय इंदिरा गांधी ने भी विचलन से राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर दी थी।

विचलन के तहत लिए एक फैसले की औपचारिक जानकारी को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा बाद में अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को दी जा सकती है। इसी विचलन के अधिकार का उपयोग करते हुए इंदिरा गांधी ने स्वतं ही नियाय लेकर राष्ट्रपति को आपातकाल के बाद देश में आपातकाल की घोषणा की गोपनीय नहीं की जाती है। इसके बाद विचलन के लिए आपातकाल के बाद देश में अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की विवादित की जाती है। यह स्वतं ही नियाय लेकर राष्ट्रपति को आपातकाल के बाद देश में अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की गोपनीय नहीं की जाती है।

विचलन के तहत लिए एक फैसले की औपचारिक जानकारी को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोर्ट के माध्यम से आपातकाल

सेल्फी के लिए प्रशंसकों की भीड़ में फंसी जानहवी

नेटिजन्स बोले- उन्हें सांस लेने की जगह तो दो
प्रैरागी

आधनत्रा जान्हवा कपूर कल अपने भाई अर्जुन कपूर के जन्मदिन में शामिल होने के लिए पेरिस से मुंबई लौटी हैं। वे पेरिस फैशन वीक में भाग लेने के लिए वहां गई थीं। अधिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपने पेरिस ट्रिप की झलकियों को भी अपने फैंस के संग साझा किया था। वहीं कल उहें एयरपोर्ट पर उनके फैंस ने सेलफी लेने के लिए घर लिया। उस दौरान जान्हवी काफी परेशान नजर आ रही थीं—जान्हवी कपूर हाल ही में फिल्म मिस्टर और मिसेज माही में नजर आई थीं। इस फिल्म में दर्शकों को उनका किरदार काफी पसंद आया था। वहीं आज इंटरनेट पर बायरल हो रहे एक वीडियो में वे एयरपोर्ट पर अपने फैंस के बीच घिरी नजर आ रही हैं। जान्हवी कपूर हाल ही में फिल्म मिस्टर और मिसेज माही में नजर आई थीं। इस फिल्म में दर्शकों को उनका किरदार काफी पसंद आया था। वहीं आज इंटरनेट पर बायरल हो रहे एक वीडियो में वे एयरपोर्ट पर अपने फैंस के बीच घिरी नजर आ रही हैं। वहीं जान्हवी कपूर जब हवाई अड्डे से बाहर निकल कर अपनी कार की ओर बढ़ने लगी तब भी वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी।



इस दरान किसा न उन्हें जन्मदिन
की मुबारकबाद भी दे दी। जान्हवी
ने उन्हें प्यार से जवाब देते हुए
कहा, आज मेरा जन्मदिन नहीं है
सोशल मीडिया पर जान्हवी कपूर
की यह वीडियो काफी वायरल हो गई
रही है। नेटिजन्स ने जान्हवी कपूर

क प्रात शुभामूल व्यक्ति किया है।
एक यूजर ने लिखा है, वे भी
इंसान हैं, उन्हें सांस लेने की जगह
तो दो। वहीं एक अन्य यूजर ने
लिखा है, अभिनेत्री होने का
मतलब नहीं है कि आप उन्हें स्पेस
ही नहीं दें।

डमाशया स पाड़त ह गना, अपना फिल्म दा नाटबुक में भी निभाया था अल्जाइमर रोगी का किरदार



जिन्होंने भासा का बड़ा उत्तर का दृश्य
की भूमिका निभाने के लिए कहा
था। मुझे नहीं पता था मां उसीनी
रोग से ग्रसित हो जाएंगी। यहाँ
बेहद आशचर्यजनक है। ऐसे कैसे
हो सकता है। मां ने उस रोल को
निभाने के लिए काफी रिसर्च
किया था ताकि फिल्म में सब
कुछ एकदम प्रमाणिक दिखे

उन्होंना तो कभी न मालिन शक्ति किया था, लेकिन हम हर दिन इसे जी रहे हैं। यह बहुत ही पीड़ादायक है। मर्मिडिया रिपोर्ट्स की मामें तो गेना रोलेंड की मां भी अल्जाइमर रोग से पीड़ित थीं। साल 2004 में गेना ने एक मैगजीन को साक्षात्कार दिया था। उस दौरान उन्होंने कहा था, मेरी

मैंने उन्हें देखने के बाद फिल्म में एली की भूमिका निभाने का निर्णय लिया था। यह मेरे लिए काफी कठिन था। अगर निक ने फिल्म का निर्देशन नहीं किया होता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यह किस्रार निभा पाती। यह एक शानदार फिल्म थी।

इडियन में काम नहीं करना चाहत थे कमल हासन, फिल्म से किनारा करने के लिए निकाली थी यह तरकीब



एक फिल्म करना चाहते हैं और उसी
दूसरी फिल्म नहीं। मेरे साथ भी
यही समस्या थी, लेकिन वह
(शंकर) कभी नहीं माने दिया।
इसलिए मैंने अपनी फीस बढ़ा
दी। फिल्म के निर्माता नहीं मान
रहे थे, लेकिन निर्देशक ने
निर्मातओं से कहा कि अगर मैं
फिल्म बनाऊंगा तो मैं इसे केवल
उन्हीं (कमल हासन) के साथ
बनाऊंगा। वह एक बहुत ही
समझदार और अनुभवी निर्देशक
की तरह इस फिल्म को लेकर
आश्वस्त थे। उनके इस गण ने

कार्यक्रम के दौरान शंकर और कमल ने यह भी पुष्टि की कि ईंडियन 2 मूल फिल्म से जुड़ी हुई है। फिल्म में कमल अपनी भूमिका को दोहराते नजर आने वाले हैं। हालांकि, फिल्म की स्टारकास्ट काफी यादा बदल गई है। इसमें सिद्धार्थ, काजल, अग्रवाल, रक्खुल प्रीति सिंह, समुथिरकानी, प्रिया भवानी शंकर और बॉबी सिम्हा शामिल हैं। शंकर ने दिवंगत अभिनेता विवेक और नेदुमुदी वेणु को बड़े पर्दे पर जीवंत करने के लिए सीधी आर्द्ध

इस्तेमाल किया है। कार्यक्रम के दौरान कमल ने इंडियन 2 के बजट के बढ़ जाने पर भी बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि कोरोना संक्रमण काल और सेटप पर हुई दुखद मौतों ने रिलीज में देरी की। अभिनेता ने प्रोजेक्ट को लेकर प्रतिबद्ध रहने वाले निर्देशक और निर्माण कंपनी लाइका प्रोडक्यूशंस की भी जमकर प्रशंसा की। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो इंडियन 2 12 जुलाई को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है।

इला की राजस्थानी सुरलहरियां फिर गूंजेगी पूरी दुनिया में

ध्रूव धाणेकर के नए अलबम को जबदस्त चर्चा

लालतानारायण द्वय जगनवा जा न आ
अलगबाट वॉयेज 2 रिलीज के लिए
तैयार है। यह साल 2015 में आएगा
वॉयेज का ही विस्तार है, जिसमें इस
दस ट्रैक सुनने को मिलेंगे। वॉयेज 2
को खास बात है कि यह भारतीय लोक संगीत और दुनिया-भर की अलग-अलग संगीत परंपराओं को आपस में जोड़ता है। इसमें बाल्कन संगीत, फ़ंकरेगे, जैज और ब्राजीलियाई सांबाशामिल हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वॉयेज 2 में श्रोताओं के भारत और दुनियाभर की संगीत शैलियों का मिश्रण सुनने का मिलेगा ध्वनि का कहना है कि संगीत स्थिर नहीं है। इसका विकास लगातार हो रहा है। वॉयेज बतौर संगीतकार दुनियाभर के संगीत को भारतीय संगीत से जोड़ने को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वॉयेज 2 के जरिए उनकी कोशिश है कि अलग-अलग शैली को खोजकर उन्हें देश के तमाम इलाकों की लोकधुनों के साथ मिलाया जाए। उदाहरण के तौर पर, सुप्रभातम ट्रैक में ड्रम, बास और हिप-हॉप इफेक्ट के साथ संस्कृत भाषा की प्रार्थनाएं सुनाई देंगी। नाचो ट्रैक में, बाल्कन हाँने और अफ्रीकी



आवाज सुनने को मिलेगी वाँयज
 2 के सभी 10 ट्रैक महिलाओं
 द्वारा ही गाए गए हैं। इसमें
 राजस्थानी गायिका इला अरुण ने
 चार गाने गाए हैं। असम की
 गायिका कल्पना पटवारी ने दो
 गानों में काम किया है। नदिनी
 श्रीकर ने सुप्रभातम को गाया है।

दशक से जुड़ी हुई हैं। जात्रा में वैशाली सामंत की सुरीली आवाज सुनने को मिलेगी वायेज 2 में इमर गीनो बैंकस, पर्क्यूशनिस्ट तौफीक कुरैशी, बास गिटारिस्ट टिम लेफेब्र और मोहिनी डे ने भी काम किया है। इसमें काम करने वाले कई घेनेकर पहले भी काम कर चुके हैं। वॉयेज 2 को 27 जून, 2024 को बाह बाह रिकॉर्ड्स पर रिलीज किया जाएगा। अलबर्म टूर का एलान होना अभी बाकी है। इसके गीतों को दुनिया भर में सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सुना जा सकेगा।

एनसाइरटा का ये नहा पता, इतहास ता और भी बहुत कुछ है, किताबों से बाहर भी है



तक। बाया, कामस्ट्रा आर फिजिक्स की ही पढ़ाई की और मुझे इस कॉम्पनीनेशन से प्यार भी था। प्यार इसलिए कि मेरे पिता के एक मित्र बहुत ही अच्छे भौतिकशास्त्री थे। मेरे माता पिता को मुझसे पढ़ाई को लेकर कोई उम्मीदें नहीं थी लेकिन पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे चीजें याद नहीं रहती थी। हमें हर चार साल में जगह बदलनी होती थी क्योंकि पापा एयरफोर्स में थे तो पढ़ाई का माध्यम भी बदल जाता था..हां, मैं उसी का जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। अध्ययन के मामले में मुझे बहुत ही कमज़ोर छात्र माना जाता था। मुझे खुद से कोई बेहतरी की

करना करना ज गति बरति थ सुररा गोपा, आज
केंद्र सरकार में संभाल रहे दो-दो मंत्रालय
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और राजनेता सुरेश गोपी आज अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 2

1958 को केरल के अलपुङ्गा में हुआ था। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने केरल की त्रिशूर लोकसभा नियमितीयों के टिकट पर जीत हासिल करके इतिहास रच दिया। उन्हें केंद्र सरकार में पर्यटन और प्रौद्योगिकीय एवं प्र

गैस राय मंत्री भी बनाया गया है। मलयालम फिल्म इंडरेट्री के सुपरस्टार और राजनेता सुरेश गोपी आज अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 26 जून, 1958 को केरल के अलप्पुड्या में हुआ था। हाल ही में हुए लोकसभा युनाव में उन्होंने केरल की त्रिशूर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल करके इतिहास रच दिया। उन्हें केंद्र सरकार में पर्यटन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राय मंत्री भी बनाया गया है। सुरेश गोपी ने साल 1965 में बौतर बाल कलाकार अपने अभिनय करियर का श्रीगणेश किया था। साल 1992 में उन्होंने थलस्तानम फिल्म में लीड रोल अदा किया था। इस फिल्म का निर्देशन शाजी कैलास ने किया था। इसके अगले ही साल उन्होंने एकलाव्यन फिल्म की, जिससे लोग उन्हें जानने लगे थे। इस फिल्म का निर्देशन भी शाजी कैलास ने ही किया था। साल 1995 में रिलीज हुई हाईवे फिल्म तो 100 से भी यादा दिनों तक सिनेमाघरों में चली थी। इस फिल्म में उन्होंने एक रॉयल अधिकारी का रोल किया था। दर्शकों ने सुरेश गोपी को पुलिस के किरदार में भी खूब पसंद किया। साल 2015 में रिलीज हुई आई फिल्म के बाद सुरेश गोपी ने एकिटंग से चार साल का लंबा ब्रेक ले लिया था। फिर 2020 में थिमिलारसन फिल्म से परेंटेपर वापसी की थी।

मिटी चीफ

जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को 12 सूत्रीय मांग पत्र भेजा, मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया।

सैकड़ों किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया

गैरव सिंधल । सिटी चीफ सहारनपुर, कलेक्ट्रेट पार्क में भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बैठक के बाद जिलाधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम 12 सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया। मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। प्रदर्शन से पहले भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य होने के कारण यहां समस्याओं का अंबार है। प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जूझ रही है इसलिए उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांटकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण किया जाए। पृथक पश्चिम प्रदेश बनने पर यहां शिक्षा और चिकित्सा अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी और यहां के शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। यहां प्रति व्यक्ति वार्षिक आय देश में ही नहीं दुनिया में



सबसे अधिक हांगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि यहां लगातार बढ़ती हुई समस्याओं का एकमात्र हल पुथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण ही है। जिसके लिए बड़े संघर्ष की तैयारी शुरू कर दी गई है। वर्मा ने कहा कि बड़े प्रदेश होने के कारण यहां कानून व्यवस्था चौपट है और किसानों, मजदूरों और गरीबों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि केंद्र की एनडाए सरकार किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाए, देश के किसानों के सभी कर्ज माफ करें, मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर किसानों को मजदूर उपलब्ध कराए, 58 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को ₹10000 प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दिलाई जाए, सभी हाईवे और सड़कों से टोल

ैक्स समाप्त किया जाए, डीजल-पैट्रोल और गैस के दाम कम किए जाए, देश के अन्नदाता किसानों की निश्चित आय करने के लिए राष्ट्रीय आय आयोग का गठन किया जाए, किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, मांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव में छोटे-छोटे कुटीर उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय सलाहकार हाफिज मुर्तजा त्यागी व राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ अशोक मलिक ने कहा कि अब देश के अन्नदाता किसान अपनी उपेक्षा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार से अपने हक्कों के लिए

लड़ाई लड़ते रहेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित नीरज कपिल व प्रदेश महामंत्री असीम मलिक ने कहा कि पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है जिसके लिए युवा शक्ति को आगे जाकर संघर्ष करना होगा। बैठक को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष मोहम्मद जहीर तुर्की ने कहा कि महानगर में संगठन को मजबूत किया जाएगा और किसानों के लिए संघर्ष जारी रहेगा बैठक में पश्चिम प्रदेश मुकियत मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुशील धारकी, प्रदेश मंत्री ऋषिपाल प्रधान गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष मांगेराम यादव, जिला उपाध्यक्ष वसीम जहीरपुर, जिला मंत्री मुकर्जी प्रधान, जिला मंत्री महबूब हसन, महानगर उपाध्यक्ष डॉक्टर कलीमउर्रहमान, हाजी बुद्धु हसन, जिला संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह एडवोकेट, मंडल उपाध्यक्ष चौधरी कुपाल सिंह, नीरापाल सिंह गुर्जर, कृष्ण पाल गुर्जर, जोगिंदर सिंह, कालू सिंह, कृष्ण कुमार, मोहम्मद अब्दुल सलाम, मनोज कुमार बबलू, सुमित वर्मा जोशी समेत सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता होरंद्र सिंह प्रधान आमकी ने की ओर संचालन आरषीय सलाहकार हाफिज मुर्तजा त्यागी ने किया।

राज्य बाल आधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने सहारनपुर में का मण्डलाय समाक्षा बढ़वा

एक युद्ध-नशे के विरुद्ध एवं भैंका से शिक्षा की ओर चलाएं अभियान : डॉ देवेन्द्र शर्मा



पत्रकार सुरक्षा एवं कल्याण परिषद का आधिवर्शन 26 जून का

बैठक का आयोजन होगा

उमश कुशवाहा। सिटी चॉक सेतना, हर वध का भात इस वध भा पत्रकार सुरक्षा एवं कल्याण परिषद का अधिवेशन जून माह की 26 जून दिन बुधवार को होना सुनिश्चित हुआ है। कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में संगठन के राष्ट्रीय अधिक्षम अंकित शर्मा एवं राष्ट्रीय सचिव विष्णु गुप्ता ने बताया कि पत्रकारों की प्रमुख मांगों और पत्रकारों के सुरक्षा के संबंध में एक समीक्षा बैठक के साथ कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित किया गया है जिसके मुख्य अतिथि श्रेयांश समदरिया विशिष्ट अतिथि कल्पना वर्मा, सतीश सुखेजा, मनोज शर्मा, मनोहर वाधवानी, संतोष सोनी, जनार्दन शुक्ला, कमलेश यादव, अमेल मोहन, संजय शाह, आशीष तिवारी, डॉक्टर अवधराज सिंह होंगे, साथ ही देश-प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों का समागम होगा। साथ ही पत्रकारों के हितार्थ विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा एवं परिचर्या का कार्यक्रम रखा जाएगा। साथ ही प्रदेश जिला एवं राष्ट्रीय

**कला ऐसी की सामने वाले को देखते ही
चंद मिनटों में उतार देती है केनवास में...**

मेहर की शैफाली को स्केच कला में महारत मिली

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ



शेफाली न बताया का अब तक उन्होंने 100 से ज्यादा स्केच बना चुकी है, शेफाली इस कला को वह विश्व स्तर पर स्थापित कर सके। उनकी एक मात्र इच्छा यह है, की उसकी इस कला से उसके कम उम्र के गरीब छात्र भी प्रशिक्षण लेकर आगे बढ़ने और अपने पैरों पर खड़ा होने का संकल्प ले। शेफाली द्वारा गरीब और छोटे बच्चों को चित्रकला अपने घर में ही सीखा रही है। और जो उनके अंदर जो कला है वो बच्चों तक पहुंचा रही है, जिससे महर झजल के साथ साथ सतना और मध्यप्रदेश का भी नाम रोशन हो सके। इसके लिए वह लगातार अपनी कला को निखारा देकर उसमे अधिक चमक पैदा कर रही है शेफाली के परिवार वालों ने अपनी बेटी को इच्छा शक्ति और पढ़ाई के साथ साथ पेंट और ब्रश के प्रति उसका प्रेरणा देख उसे आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया, शेफाली के द्वारा स्केच बना के सोसल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम आईडी में शेयर किया जाता है।

दुकान और गोदामों को सील किए जाने पर करा कार्यालयों का घेराव

कटुता पदार्थ के स्टोर बना करने की कठिनी जिले के सैकड़ों कबाडियों अपने परिजनों के साथ एसडीएम और नगर निगम कार्यालय का धेराव करने पहुंचने जिसके साथ एक समाज सेवक अपने पूरे शरीर पर जंजीर रखते हुए जकड़ पहुंचा था सभी ने जिला प्रशासन का अर्थी जलसू निकात एसडीएम कार्यालय और उसके बाद नगर निगम कार्यालय पहुंच थे। ये सभी जिला प्रशासन द्वारा इनकी कबाडियों की दुकान और गोदामों को सील किए जाने नाराज थे। ये सभी जिला प्रशासन द्वारा शहर के अंदर बने कबाडियों की दुकान व गोदामों को बंद कर की कार्यवाही से नाराज हैं जिन्हें कुछ दिन पहले ही जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। नाराज सभी



न की इस फ जिला स निकाल लय पहुंचे बाद सभी ना दे दिया गंग थी की ने के पहले

कटनों में कुरुत्यात आरोपों किस्सू तिवारी को न्यायालय ने सुनाई सजा

याहू | मिटी चीफ |

कट्टनी के जिस फैसले का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वह फैसला आखिरकार आज न्यायालय ने सुना ही दिया। हत्याकांड के कुख्यात आरोपी किस्सू तिवारी को न्यायालय ने घटनाक्रम के 37 साल बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कुख्यात आरोपी किस्सू तिवारी काफी समय से पर फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने आरोपी को 22 मई को अयोध्या से गिरफ्तार कर कट्टनी न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय द्वारा आज किस्सू



भट्टे में डाल देने के मामले में जिला न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। सोमवार को मामले में फैसला आने की संभावना थी। सुबह से जिला न्यायालय में पुलिस बल तैनात रहा। दोपहर बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए किस्सू तिवारी को मामले में जहां दो धाराओं में दोषमुक्त किया है तो वहीं हत्या के मामले में उसे दोषी पाया है जिसमें कटनी के अलावा जबलपुर व इंदौर में भी उसने अपराध किए थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के वर्ष 1987 में राजेन्द्र डेऊँ नामक युवक को किस्सू उसके घर से पार्टी के लिए लेकर गया था और खाना खाने के बाद ढाबे में उसके साथ मारपीट की थी। साथ ही दस किमी दूर ले जाकर छूने के जलते भट्टे में उसे झोंक दिया था। दूसरे दिन उसका जला हुआ शव भट्टे से पुलिस ने बरामद किया था। सन 2021 में डेऊँ की हत्या में डाल देने के मामले में जिला न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। सोमवार को मामले में फैसला आने की संभावना थी। सुबह से जिला न्यायालय में पुलिस बल तैनात रहा। दोपहर बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए किस्सू तिवारी को मामले में जहां दो धाराओं में दोषमुक्त किया है तो वहीं हत्या के मामले में उसे दोषी पाया है जिसमें कटनी के अलावा जबलपुर व इंदौर में भी उसने अपराध किए थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के वर्ष 1987 में राजेन्द्र डेऊँ नामक युवक को किस्सू उसके घर से पार्टी के लिए लेकर गया था और खाना खाने के बाद ढाबे में उसके साथ मारपीट की थी। साथ ही दस किमी दूर ले जाकर छूने के जलते भट्टे में उसे झोंक दिया था। दूसरे दिन उसका जला हुआ शव भट्टे से पुलिस ने बरामद किया था। सन 2021 में डेऊँ की

